



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 970]
No. 970]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 23, 2003/कार्तिक 1, 1925
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 23, 2003/KARTIKA 1, 1925

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2003

का.आ. 1231 (अ).—केंद्रीय सरकार एतद्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 20 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवन समिति की सिफारिश पर, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एन. कपूर को उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 70 वर्ष की आयु को प्राप्त हो जाने तक, जो भी पहले हो, समय—समय पर यथा संशोधित उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में निर्धारित निवंशनों और शर्तों पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1(5)/2001-सीपीयू]

सतवन्त रेड्डी, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2003

S.O. 1231(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) read with Sub-section (3) of Section 20 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government, on the recommendation of the Selection Committee, hereby appoints Mr. Justice S.N. Kapoor, Retd. Judge of Delhi High Court, as a whole-time member of the National Consumer Disputes Redressal Commission with effect from the date on which he assumes the charge of his office, for a period of five years or upto the age of 70 years, whichever event occurs earlier, on the terms and conditions prescribed in the Consumer Protection Act, 1986 read with the Consumer Protection Rules, 1987 as amended from time to time.

[F. No. 1(5)/2001-CPU]

SATWANT REDDY, Addl. Secy.